भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 818
07 फरवरी, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए

मत्स्यन, पशुपालन और डेयरी परियोजनाएं

818. डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे:

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत मत्स्यन, पशुपालन और डेयरी परियोजनाओं की स्थापना के संबंध में महाराष्ट्र सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;
(ख) गत तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में मत्स्यन, पशुपालन और डेयरी क्षेत्र के विकास के लिए सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं का ब्यौरा क्या है;
(ग) इन योजनाओं से अब तक लाभान्वित हुए किसानों की कुल संख्या कितनी है;
(घ) क्या सरकार उक्त क्षेत्र में विकास दर के लक्ष्य को प्राप्त करने में विफल रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और
(ङ) देश में पशुपालन और मत्स्यन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए सुधारात्मक कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री

(श्री परशोत्तम रूपाला)

(क) से (ङ): मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिए महाराष्ट्र राज्य सहित देश में निम्नलिखित योजनाओं और कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर रहा है :

1. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई),
2. मात्स्यिकी और जलकृषि अवसंरचना विकास निधि (एफआईडीएफ)
3. राष्ट्रीय गोकुल मिशन (आरजीएम),
4. राष्ट्रीय पशुधन मिशन (एनएलएम),
5. राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (एनपीडीडी),
6. डेयरी प्रसंस्करण और अवसंरचना विकास निधि (डीआईडीएफ),
7. डेयरी सहकारी समितियों और किसान उत्पादक संगठनों (एसडीसीएफपीओ) को सहायता
8. उद्यमिता विकास और रोजगार सृजन (ईडीईजी), और
9. पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एलएचडीसीपी)।

मात्स्यिकी क्षेत्र के संबंध में, मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्षों 2020-21, 2021-22 और 2022-23 के दौरान राज्य में मात्स्यिकी और जलीय कृषि क्षेत्र के विकास के लिए 355.32 करोड़ रुपये केंद्रीय हिस्से के साथ कुल 792.32 करोड़ रुपये की लागत से महाराष्ट्र सरकार के प्रस्तावों को मंजूरी दी है जिससे मत्स्य किसानों सहित अनुमानित 13603 लाभार्थी लाभान्वित हुए। इसके अलावा, मात्स्यिकी और जलकृषि अवसंरचना विकास निधि के अंतर्गत, मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने अब तक महाराष्ट्र राज्य को 943.69 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय से परियोजना प्रस्तावों को मंजूरी दी है, जिसमें 3% तक के ब्याज सबवेंशन के रूप में रियायती वित्त प्रदान करने के लिए निजी लाभार्थियों के प्रस्ताव शामिल हैं।

डेयरी क्षेत्र के संबंध में, राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (एनपीडीडी) योजना के अंतर्गत, महाराष्ट्र के लिए 45.07 करोड़ रुपये के केन्द्रीय हिस्से के साथ और 49.47 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय से तीन परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। अब तक 31.92 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है। डेयरी प्रसंस्करण और अवसंरचना विकास निधि (डीआईडीएफ) के अंतर्गत , महाराष्ट्र राज्य के लिए 488.33 करोड़ रूपये की कुल लागत पर 2 परियोजनाएं और ब्याज सबवेंशन प्रदान करने के लिए 290.66 करोड़ रूपये की ऋण राशि स्वीकृत की गई है। 31-12-2022 तक महाराष्ट्र में डीआईडीएफ के अंतर्गत 1.9 लाख किसान अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित हुए हैं। इसके अलावा, डेयरी गतिविधियों में संलग्न डेयरी सहकारी समितियों और किसान उत्पादक संगठनों (एसडीसीएफपीओ) को सहायता देने वाली केंद्रीय क्षेत्र की योजना के अंतर्गत , राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) ने महाराष्ट्र राज्य में दो दुग्ध संघों के लिए वर्ष 2020-21 के लिए 4.40 करोड़ रुपये और वर्ष 2021-22 के लिए 4.71 करोड़ रुपये का ब्याज सबवेंशन जारी किया है।

पशुपालन क्षेत्र के संबंध में, पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (एएचआईडीएफ) के अंतर्गत, महाराष्ट्र राज्य के लिए 1325.61 करोड़ रुपये की कुल लागत पर 36 परियोजनाएं और ब्याज सबवेंशन प्रदान करने के लिए 947.72 करोड़ रुपये की ऋण राशि स्वीकृत की गई है। इसके अलावा, राज्य सरकार ने पशुधन बीमा के लिए भी एक प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया है और उसे अनुमोदित कर दिया गया है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन (आरजीएम) के अंतर्गत, महाराष्ट्र को 68.96 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एलएचडीसीपी) के अंतर्गत, महाराष्ट्र में 1,47,11,259 पशुओं को फुट एण्ड माउथ डिसीस (एफएमडी) के लिए पहले दौर का टीका लगाया गया है, 1,68,78,945 पशुओं को दूसरे दौर का एफएमडी टीका लगाया गया है, ब्रुसेला के लिए 3,74,523 पशुओं का टीकाकरण किया गया है और 43,263 पशुओं का पेस्ट डेस पेटिट्स रूमिनेंट्स (पीपीआर) के लिए टीकाकरण किया गया है। मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों (एमवीयू) की स्थापना और सुदृढ़ीकरण के लिए महाराष्ट्र राज्य को सहायता दी गई है और ऐसे 80 एमवीयू को मंजूरी दी गई है और 12.90 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की गई है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम के अंतर्गत महाराष्ट्र के 20.69 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं।

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी क्षेत्र हाल के वर्षों में तेजी से विकास का प्रदर्शन कर रहे हैं। महाराष्ट्र का मत्स्य उत्पादन 2020-21 में 5.23 लाख टन से बढ़कर 2021-22 के दौरान 5.89 लाख टन हो गया है, जो वर्ष 2020-21 की तुलना में 12.6% की वृद्धि दर्ज करता है। महाराष्ट्र के पशुपालन क्षेत्र में विकास दर लक्ष्य आशावादी रहा है, यह 2012-13 में 3.8% से बढ़कर 2020-21 में 11% हो गई है।

*****